संख्या-33/2019/680/12-5-2019-ब-04/2018

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः: दिनांकः: 03 जून, 2019**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण,103-भूमि सुधार तथा विकास, 09-पं० दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू०सं०लेखा/पं०दी०उ०कि०स०यो०/वित्तीय स्वीकृति/30डी/2019-20, दिनांक 22 मई,2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं० दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 11450.00 लाख के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार रू0 6190.50 लाख (रूपये इकसठ करोड़ नब्बे लाख पचास हजार मात्र)की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0में)

मानक मद	प्राविधान 2019-20	स्वीकृत धनराशि
04-यात्रा व्यय	20.00	10.00
08- कार्यालय व्यय	25.00	12.50
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	20.00	10.00
15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	35.00	17.50
27- सब्सिडी	931.00	931.00
42- अन्य व्यय	10349.00	5174.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय	50.00	25.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20.00	10.00
योग	11450.00	6190.50

(रूपये इकसठ करोड़ नब्बे लाख पचास हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेनिशयल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्यसरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्यप्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उनहीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योकिं धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्टर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31.01.2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 01.04.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-285/दस-2012-10(29)/2011टीसी-11,दिनांक 29.05.2012 द्वारा समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जाय। इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

7- कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलबध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

8. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, कृषि एवं संबंधित नोडल अधिकारी का होगा।

9- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण,103-भूमि सुधार तथा विकास, 09-पं० दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 33/2019/680(1)/12-5-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार- प्रथम/ द्वितीय (आडिट/सिविल), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ की वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके,द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ संबंधित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन प्रति की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. अपर कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण,कृषि भवन, उ०प्र०,लखनऊ।
8. वित्त ई-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मंजू लता सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in